



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252948
CG-DL-E-14032024-252948

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1197]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 12, 2024/फाल्गुन 22, 1945

No. 1197]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 12, 2024/PHALGUNA 22, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

[दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

का.आ. 1259(अ).—सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, तथा फायदाग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे ही प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और, भारत सरकार में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है) दिव्यांगजनों को एक केंद्रीय सेक्टर स्कीम के रूप में सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद और या फिटिंग के लिए सहायता स्कीम (एडिप) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) एक केंद्रीय स्कीम के रूप में प्रशासन कर रहा है, जिसमें राष्ट्रीय संस्थानों, समेकित क्षेत्रीय केंद्रों, भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को), जिला दिव्यांगजन पुनर्वास केंद्रों, राज्य दिव्यांग विकास निगमों, अन्य स्थानीय निकायों और गैर-सरकारी संगठनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से पात्र दिव्यांगजनों को टिकाऊ, परिष्कृत और वैज्ञानिक रूप से विनिर्मित, आधुनिक, मानक सहायक यंत्र और उपकरण प्रदान किए जाते हैं।

और, इस स्कीम के अधीन, मौजूदा स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र दिव्यांगजनों (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदाग्राही कहा गया है) को सहायक यंत्र और सहायक उपकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्रसुविधा कहा गया है) प्रदान किए जाते हैं;

और, स्कीम के कार्यान्वयन में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित हैं;

और, इस विभाग ने पूर्व में तारीख 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 711(अ) (एफ.सं.4-2(32)/2016-डीडी-1) के द्वारा सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांगजनों को सहायता (एडिप) के लिए आधार को एक पहचान दस्तावेज के रूप में अधिसूचित किया है;

अब, इसलिए, तारीख 3 मार्च, 2017 की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 711 (अ) (एफ.4-2(32)/2016/डीडी-1) के अधिक्रमण में, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के अनुसरण में, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित अधिसूचित करती है: अर्थात् -

1. (क) स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से यह अपेक्षित होगा कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन करवाए;

(ख) इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यक्ति को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है, या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, को इस स्कीम के लिए रजिस्ट्रीकरण करने से पहले आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परंतु कि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अभिप्राप्त करने का हकदार हो, और ऐसा व्यक्ति आधार नामांकन के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) वेबसाइट www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध है) पर जाएगा ;

(ग) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, विभाग को अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से उन फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं किया है और यदि संबंधित ब्लॉक या तालुका या तहसील में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है, तो विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वय से या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करेगा :

परंतु कि ऐसे व्यक्ति को आधार संख्यांक नियत किए जाने तक, इस स्कीम के अधीन प्रसुविधाएं निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए दी जाएंगी, अर्थात्:-

(क) यदि उसने नामांकन किया है, तो उसकी आधार नामांकन पहचान पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात् :-

(i) फोटो के साथ बैंक या डाकघर पासबुक; या

(ii) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) राशन कार्ड; या

(v) मतदाता पहचान दस्तावेज; या

(vi) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) कार्ड; या

(vii) किसान फोटो पासबुक; या

(viii) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकरण द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(ix) राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा शासकीय लेटर हेड पर जारी ऐसे व्यक्ति का फोटोयुक्त पहचान प्रमाण दस्तावेज; या

(x) विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परंतु कि उपरोक्त दस्तावेजों को उस प्रयोजन के लिए विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. इस स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाजनक रूप से प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुनिश्चित करने के लिए सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा कि फायदाग्राहियों को स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में जागरूक करने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जाएगा।
3. उन सभी मामलों में, जहां खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से फायदाग्राहियों के आधार अधिप्रमाणन असफल हो जाते हैं, वहां निम्नलिखित उपचारात्मक तंत्र अंगीकृत किए जाएंगे, अर्थात् –
 - (क) खराब फिंगरप्रिंट गुणवत्ता की दशा में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन सुविधा को अंगीकृत किया जाएगा, और विभाग, अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्रदान करने के लिए आईरिस स्कैनर या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के साथ-साथ फिंगर-प्रिंट अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगा;
 - (ख) फिंगरप्रिंट या आईरिस स्कैन या चेहरे (फेस) के अधिप्रमाणन के माध्यम से बायोमैट्रिक अधिप्रमाणन सफल नहीं होने की दशा में जहां भी संभव और स्वीकार्य हो, यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन किए जाएंगे;
 - (ग) अन्य सभी दशाओं में, जहां बायोमेट्रिक या आधार वन टाइम पासवर्ड या समय-आधारित वन-टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां स्कीम के अधीन वास्तविक (फिजिकल) आधार दस्तावेज के आधार पर प्रसुविधाएं दी जा सकती हैं, जिसकी अधिप्रमाणिकता आधार दस्तावेज पर मुद्रित त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) कोड के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और विभाग द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया कोड रीडर की आवश्यक व्यवस्था अपनी कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से सुविधाजनक अवस्थानों पर प्रदान की जाएगी।
4. यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस स्कीम के अधीन कोई भी ईमानदार फायदाग्राही अपनी देय प्रसुविधाओं से वंचित न हो, विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से, 19 दिसंबर, 2017 (<https://dbtbharat.gov.in/> पर उपलब्ध) के प्रत्यक्ष प्रसुविधा हस्तांतरण मिशन, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी -26011/04/2017-डीबीटी में यथानिर्दिष्ट अपवाद रखरखाव (एक्सेप्शन हैंडलिंग) तंत्र का पालन करेगा।
5. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रवृत्त होगी।

[सं. पी-13013/24/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

S.O. 1259(E).—Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan) Ministry of Social Justice and Empowerment, (hereinafter referred as the Department) in the Government of India is administering the Scheme of Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP) as a Central Sector Scheme (hereinafter referred to as the Scheme) wherein durable, sophisticated and scientifically manufactured, modern, standard aids and appliances are provided to eligible Persons with Disabilities implemented through National Institutes, Composite Regional Centres, Artificial Limbs Manufacturing Corporation of India(ALIMCO), District Disability Rehabilitation Centres, State Handicapped Development Corporations, other local bodies and Non-Governmental Organisations(hereinafter referred to as the implementing agencies)

And whereas, under the Scheme, Aids and assistive devices are provided (hereinafter referred to as benefits) is given to eligible persons with disabilities (hereinafter referred to as beneficiaries) as per the extant scheme guidelines ;

And whereas, the implementation of the Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

And whereas, this Department has earlier notified Aadhaar as an identity document for Assistance to Persons with Disabilities for Purchase/Fitting of Aids/Appliances (ADIP) vide Notification No. S.O. 711(E) dated 3rd March, 2017 (F.No.4-2(32)/2016-DD-I);

Now, therefore, in supersession of Notification No. S.O.711 (E) dated 3rd March, 2017 (F.No.4-2(32)/2016/DD-I), in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (*hereinafter referred to as the said Act*), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (a) an individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication;
- (b) any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make an application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act, and such individual shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar;
- (c) as per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of Unique Identification Authority of India (UIDAI) or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :—

- a. if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- b. any one of the following documents, namely:
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identity Card; or
 - (vi) MGNREGA card; or
 - (vii) Kisan Photo passbook; or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having a photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letterhead; or
 - (x) any other document as specified by the Department:

Provided, further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for that purpose.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, an iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, and the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in a seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password with limited time validity, as the case may be, shall be offered;

- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password or Time-based One-Time Password authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of a physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of QR code reader shall be provided at convenient locations by the Department through its Implementing Agency.
4. In order to ensure that no bonafide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the Department through its Implementing Agency shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India No. D-26011/04/2017-DBT, dated the 19th December 2017 (available on <https://dbtbharat.gov.in/>).
5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all the States and Union territories.

[No. P-13013/24/2023-UDID/IT/STATISTICS]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.